

29 नवम्बर को कांग्रेस मंथन करेगी, हरियाणा व महाराष्ट्र की हार के बारे में

उस दिन आहत सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में राहुल गांधी पर दबाव होगा कि वे कांग्रेस की भावी नीति के बारे में दिशा व राह तय करके बतायें

-रेणु मिश्र-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवम्बर कांग्रेस 29 नवम्बर को हरियाणा और महाराष्ट्र में अपनी हार पर मंथन एवं चिन्तन करेगी। इन दोनों राज्यों में अपनी जबरदस्त हार एवं वहाँ की राजनैतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिये कांग्रेस वकिंग कमेटी की मीटिंग में इन बिन्दुओं पर चर्चा होगी है।

इस समय राहुल गांधी पर भारी दबाव है कि वे पार्टी के आगे के रास्ते की रूपरेखा प्रस्तुत करें तथा बतायें कि पराजयों को रोकने तथा विभिन्न समस्याओं का सामना करने के सम्बंध में पार्टी की क्या योजनाएं हैं।

सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हैं कि विभिन्न राज्यों तथा लोकसभा चुनावों में एक के बाद एक हुई हारों के पीछे असली दोषी ई.वी.एम. हैं।

लेकिन प्रतिष्ठा बचाने के लिये, उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे ई.वी.एम. के मुद्दे को न केवल उठावें, बल्कि आगे भी बढ़ायें।

शनिवार को, महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आने के बाद, जयराम रमेश

उन पर यह भी दबाव है, कि पार्टी की हार का ठीकरा ई.वी.एम. के माथे पर फोड़े, इसीलिए जयराम रमेश व पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह ध्योरी चलाई थी। पर राहुल इस सोच के बारे में पूर्णतया सहमत नहीं लगते हैं।

पर, मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने बेबाक यह कहा है कि, पार्टी को ई.वी.एम. मशीन पर विश्वास नहीं है। यह ही पार्टी का अधिकृत सोच बनता नजर आ रहा है, और राहुल को भी यह सोच प्रतिपादित करनी होगी, मन से या बेमन से।

जैसा कि स्पष्ट नजर आ रहा है, महाराष्ट्र की हार के बाद राहुल व प्रियंका लगभग चुप ही हैं, इस हार के मुद्दे पर। पर राहुल को अब सख्त निर्णय लेने ही पड़ेगे, जिससे पार्टी जीवित रह सके। अब ये सख्त निर्णय ज्यादा दिन नहीं टाले जा सकते।

और पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की तथा उन्होंने आगे-अधरे मन से ई.वी.एम. पर दोषारोपण किया। लेकिन इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि पार्टी साफ तौर पर एक रुख अपनाये, जो चाहे इधर हो या उधर, तथा अपनी आदत के अनुसार, बुलमुल बातें करने

में अपना समय बर्बाद न करे। इस संदर्भ में, यह याद दिलाता उचित होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक सुस्पष्ट बयान दिया कि पार्टी को ई.वी.एम. पर जरा भी विश्वास नहीं है तथा चुनाव मतपत्रों के जरिये होने चाहिये।

पार्टी का यही रुख नजर आ रहा है तथा इसकी गूँज 29 नवम्बर को सी.डब्ल्यू.सी. की मीटिंग में सुनाई दे सकती है।

इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव तथा शरद पवार जैसे नेता का यह विचार पहले से ही है तथा ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि पार्टी इस मामले में गठबंधन के अन्य पार्टियों के साथ गंभीरता से चर्चा कर सकती है। उधर, ममता बनर्जी तथा टी.एम.सी. नेता कल्याण बनर्जी राहुल गांधी तथा कांग्रेस पर खुलकर कटाक्ष कर रहे हैं।

साफ बात यह है कि ममता इंडिया गठबंधन की नेता बनना तथा गठबंधन में अपनी चलाना चाहती हैं। राहुल इस हार के बाद खामोश हैं तथा प्रियंका गांधी ने भी महाराष्ट्र को लेकर कोई बयान नहीं दिया है।

ये हार गठबंधन के अन्दर राहुल गांधी की स्थिति तथा सोच को कमजोर कर रही है। पार्टी नेताओं ने उन्हें सलाह दी है कि वे दृढ़ और दूरगामी निर्णय लें, पुराने निकृष्ट नेताओं को हटाएँ, अच्छा प्रदर्शन न करने वाले (नॉन फरफॉर्मर्स) (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोरेन 28 नवम्बर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवम्बर झारखंड के राज्यपाल सन्तोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन 28 नवम्बर को राँची में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिये आमंत्रित किया है। यह मुख्यमंत्री के रूप में उनका तीसरा कार्यकाल होगा क्योंकि फरवरी 2024 में अपनी गिरफ्तारी के बाद, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था तथा सत्ता की बागडोर चम्पई सोरेन को सौंप दी थी। लेकिन वे जुलाई 2024 में फिर से मुख्यमंत्री बन गये थे।

हेमन्त सोरेन ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आमंत्रित किया।

अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (जे.एम.एम.) की चुनावी सफलता के बाद, हेमन्त ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिये प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है। उन्होंने मंगलवार को यहाँ प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की।

वे अपने मंत्रालय में मंत्री पदों के लिये कांग्रेस तथा लालू प्रसाद के राष्ट्रीय जनता दल (आर.जे.डी.) के वरिष्ठ नेताओं से बात कर रहे हैं। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘पूर्व सी.जे.आई. चन्द्रचूड की वजह से एम.वी.ए. की हार हुई’

शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने अपने एक्शन से दल बदल का रास्ता खुला छोड़ दिया

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवम्बर शिवसेना (यू.बी.टी.) का मानना है कि हाल ही में संपन्न हुए राज्य विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एम.वी.ए.) का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि पार्टी में विभाजन के बाद, संयुक्त सेना विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की याचिकाओं पर जस्टिस डी.वाय. चन्द्रचूड ने निर्णय नहीं लिया। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने आरोप लगाया कि “अपने एक्शन से भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने राजनीतिक दलबदल के लिए दरवाजे खुले छोड़ दिए और राजनेताओं के मन से कानून का भय खत्म कर दिया।”

जस्टिस चंद्रचूड ने इस बात की प्रतिक्रिया में कहा है, “पूरे वर्ष हम मौलिक संवैधानिक मामलों से निपटते रहे, जिनमें से कुछ 20 साल से लंबित हैं। नौ जजों, सात या पांच जजों की बैंच इन केसों पर फैसला लेने के लिए बैठती

संजय राउत ने कहा कि इससे नेताओं में कानून का डर खत्म हो गया।

पूर्व सी.जे.आई. चन्द्रचूड ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि क्या अब राजनैतिक दल तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट किस केस की सुनवाई करे, माफ कीजिए यह “चॉइस” सुप्रीम कोर्ट की है।

ज्ञातव्य है कि, जनवरी 2022 में जब शिवसेना का विभाजन हुआ था तब उद्भव ठाकरे ने बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से फैसला करने को कहा था, जिन्होंने इस वर्ष जनवरी में शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित कर दिया था।

हैं। अब, क्या किसी राजनीतिक दल को यह निर्णय लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट किस केस की सुनवाई करे? सारी, यह चॉइस सुप्रीम कोर्ट की है।”

जनवरी 2022 में, अविभाजित शिवसेना में एकनाथ शिंदे घटक के

विद्रोह के बाद विभाजन हो गया और उद्भव ठाकरे को हटा कर शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। ठाकरे ने दलबदल करने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के लिए याचिका दायर की, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘अजित पवार से गठबंधन कर सरकार बनाएं’

भाजपा नेतृत्व ने देवेन्द्र फड़नवीस को स्पष्ट निर्देश दिया

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवम्बर भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व ने मंगलवार को अपने नेता देवेन्द्र फड़नवीस से कहा कि अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पद से हटने से इन्कार करें, तो वे (फड़नवीस) मुख्यमंत्री पद के लिये अपना दावा प्रस्तुत कर दें। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें सलाह दी कि वे अजित पवार के नेतृत्व वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) से गठजोड़ कर लें।

पार्टी सूत्रों ने कहा कि अजित पवार ने इस आइडिया को मान लिया है, क्योंकि भाजपा 132 सीटें जीत कर मजबूत स्थिति में है तथा वह अजित पवार गुट के समर्थन से बहुमत का आँकड़ा, जो 145 सीटों का है, प्राप्त कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि अन्य पार्टियों के कुछ “मूक” समर्थक भी

बांग्लादेश में इस्कों प्रमुख चिन्मय प्रभु गिरफ्तार

ढाका, 26 नवंबर बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। चटगांव इस्कों पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्णन दास की गिरफ्तारी के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध

हिंदू समुदाय ने सड़कों पर विरोध जताया तो जमात और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों ने उन पर हमला किया, हमले में 50 से ज्यादा हिन्दू घायल हो गए।

में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए, तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में हिंदू समुदाय के 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ढाका के शाहबाग में शांतिपूर्ण सभा के दौरान (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चर्चा है कि महायुति गठबंधन में दरार पड़ गई है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के पद पर दावा छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

अगर भाजपा अजित पवार की एन.सी.पी. के साथ ही गठबंधन करके सरकार बनाती है, तो भी उसके पास पूर्ण बहुमत है।

अजित पवार ने यह बात मान ली है कि भाजपा के पास बहुमत है तो गठबंधन को वही लीड करेगी।

फड़नवीस को समर्थन दे सकते हैं।

फड़नवीस पहले 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं तथा 2019 में भी अजित पवार के साथ हुये अल्पकालिक गठबंधन के साथ वे बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। राज्य में हुये इन चुनावों, जिनमें भाजपा ने रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन किया है, में उनके नेतृत्व को पार्टी की रणनीति के एक निर्णायक कारक होने का श्रेय दिया जा रहा है।

गठबंधन के अन्दर पैदा हो रही चिन्ताओं का समाधान करने के लिये, ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि भाजपा शिंदे तथा पवार, दोनों को ही उपमुख्यमंत्री पद को पेशकश करेगी। लेकिन, मंत्री पद के लिये विभागीय और संसाधन आवंटन से सम्बन्धित मुद्दों का अभी समाधान नहीं हुआ है तथा इस दिशा में बातचीत चल रही है। शिंदे-समर्थक महत्वपूर्ण मंत्रालयों के लिये दबाव बना रहे हैं।

जे.डी.सी. आनंदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

जयपुर, 26 नवंबर जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने आयोग के आदेश की पालना नहीं करने पर जयपुर विकास प्राधिकरण की आयुक्त, आई.ए.एस. आनंदी के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। आयोग ने पुलिस कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि वह आनंदी को गिरफ्तार कर 18 दिसंबर तक आयोग

जिला उपभोक्ता आयोग ने 10 नवम्बर 2023 के निर्देश की पालना नहीं करने पर जे.डी.सी. के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

के समक्ष पेश करे। आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश राज सिंह अजमेय के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, जे.डी.ए. की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश की पालना के लिए समय मांगा गया, जिसे आयोग ने खारिज करते हुए जे.डी.सी. (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कनक भवन के मालिकाना हक से जुड़े मामले में महाराज पद्मनाभ को राहत दी सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संपत्ति से जुड़े किसी भी मुकदमे की सुनवाई हाईकोर्ट में नहीं होगी

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 26 नवम्बर सेंट्रल पार्क में लक्ष्मी निवास होटल के भीतर निर्मित कनक भवन के मालिकाना हक को लेकर अदालतों में चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किये हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट उक्त मामले में दायर अपीलों और आवेदनों पर सुनवाई न करे। न्यायाधीश जे.बी.पारदीवाला और न्यायाधीश आर.महादेवन ने यह आदेश महाराज पद्मनाभ की ओर से विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) पर सुनवाई करते हुए दिये। इस मामले में याचिकाकर्ता महाराज पद्मनाभ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ मिश्रा और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वंशजा शुक्ला और सहायक वकील शाश्वत पुरोहित की ओर से पत्रों की गई।

मामले के तथ्यों के अनुसार, वर्ष 2003 में मृदुल गुप्ता व रामशरण गुप्ता की ओर से सेशन जज के समक्ष कनक भवन के 1986 में बेचान को लेकर

जैसा कि विदित है कि कनक भवन तथा लक्ष्मी विलास होटल और सेंट्रल पार्क की संपत्ति जयपुर के भारत में विलय के बाद सरकारी संपत्ति बन गई थी। वहीं रामबाग, लिलिपूल और उसके आसपास की संपत्ति “कोवोर्नेट” के अनुसार राजपरिवार की संपत्ति है।

उल्लेखनीय है कि कनक भवन के बेचान से संबंधित विवाद कई बार निचली अदालत, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक गये हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में आदेश में यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस संपत्ति के बेचान के लिये अनुबंधन अमान्य है।

वकीलों का कहना है कि हाईकोर्ट में इस केस में रामशरण गुप्ता व अन्य की ओर से संपत्ति के मूल मालिक ब्रिगेडियर भवानी सिंह के वंशजों को जोड़ने के लिये आवेदन इसलिये पेश किया गया ताकि उनके निधन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वह मामला निष्फल या निरस्त ना हो

सेल डीड की क्रियान्वित के लिये 2005 में निचली अदालत ने इस मामला दायर किया गया परंतु वर्ष 2005 में निचली अदालत ने इस मामले को खारिज करते हुए कहा कि

हाईकोर्ट 1993 में इस संपत्ति के बेचान के अनुबंध को निरस्त कर चुका है। इस बीच, राजस्थान हाईकोर्ट में वर्ष 2003 में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें उक्त संपत्ति (कनक भवन) पर से अतिक्रमण हटाने की गुहार की गई। परंतु वर्ष 2010 में इस जनहित याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने पुनः अपने आदेश को दोहराया कि 1986 में किया गया बेचान का अनुबंध अमान्य है।

तत्पश्चात, रामशरण गुप्ता व अन्य ने हाईकोर्ट के 2010 के आदेश से आहत होकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। उल्लेखनीय है कि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान ही वर्ष 2011 में, इस संपत्ति के पूर्व मालिक ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह का निधन हो गया।

पाठकों को बता दें कि कनक भवन तथा लक्ष्मी विलास होटल और सेंट्रल पार्क की संपत्ति राज पुताना के सामंती (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सड़कों पर उतरे इमरान समर्थक

इस्लामाबाद, 26 नवंबर जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों द्वारा किए गए प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के कारण अर्धसैनिक बल के चार जवान और दो पुलिसकर्मी

इमरान खान की रिहाई को लेकर सड़कों पर उतरे लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया, सरकार ने सेना तैनात की और उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश दिया।

मारे गए हिंसा में 100 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए हैं। इस हिंसा के कारण, सरकार ने राजधानी में सेना तैनात करने के साथ ही, आदेश दिए गए हैं कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मार दी जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तेलंगाना सरकार ने फटाफट अडानी ग्रुप का सौ करोड़ रुपये का चैक लौटाया

यह चैक गौतम अडानी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवन्त रेड्डी को दान के रूप में दिया था, तेलंगाना “स्किल डवलपमेंट युनिवर्सिटी” बनाने के लिए

चैक वापसी का निर्णय इस बात का प्रमाण है, कि राहुल गांधी व कांग्रेस अडानी ग्रुप के खिलाफ अपना विरोध और तीव्र करेंगे, संसद व उसके बाहर भी।

विपक्ष ने, विशेषकर बी.आर.एस. के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने कटाक्ष किया, एक तरफ तो राहुल गांधी, मोदी व अडानी के गहरे सम्बंधों को “मोडानी” कहकर खिल्ली उड़ते हैं, दूसरी ओर तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रेवन्त रेड्डी, अडानी से मित्रता करके सौ करोड़ रुपये का दान लेते हैं, तो क्या नये प्रेम को “रेवडानी” और इस मित्रता को राहुल गांधी का प्रश्रय प्राप्त है, अतः क्या राहुल अडानी सम्बन्धों के “रागाडानी” नहीं कहना चाहिए।

यंग इंडिया स्किल डवलपमेंट युनिवर्सिटी के लिए किसी से भी अनुदान नहीं लेगी, इसमें अडानी की कम्पनी भी शामिल है।

सोमवार को राज्य सरकार ने अडानी ग्रुप

को लिखा था कि उनकी सरकार स्किल डवलपमेंट युनिवर्सिटी के लिए उनका 100 करोड़ रु. का अनुदान स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने

सोमवार को राज्य सरकार ने अडानी ग्रुप

और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए राज्य में ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निविदा जारी की जानी चाहिए। एक सही व्यवस्था व

लोकतांत्रिक तरीके से टैंडर दिए जाने चाहिए, चाहे ये अंबानी को मिले या अडानी या टाटा को। स्किल युनिवर्सिटी के लिए अडानी ग्रुप की ही तरह कई अन्य कम्पनियों ने भी फंड देने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि “मैं यह निर्णय दोहराता हूँ कि राज्य सरकार अडानी ग्रुप से 100 करोड़ रु. का फंड नहीं लेगी।”

तेलंगाना के स्पेशल चीफ सैक्रेटरी और इंडस्ट्रियल प्रमोशन के सरकारी आयुक्त जयेश रंजन ने अडानी फाउण्डेशन की अध्यक्ष डॉ. प्रीति अडानी को सूचना दी है कि राज्य यंग इंडिया स्किल युनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रु. का अनुदान देने की पेशकश के लिए आपका आभारी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सार-समाचार

महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समिति गठित

अजमेर, (कास)। अजमेर डिस्कॉम में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक समिति गठित की गई है। इस समिति में अजमेर डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। समिति के सदस्यों में शामिल सुरभि पारीक वरिष्ठ लेखाधिकारी लेखा अजमेर डिस्कॉम अलका जैन अध्यक्ष ज्ञानम एजुकेशन एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी अजमेर, दीपक मंगल कार्मिक अधिकारी मुख्या अजमेर डिस्कॉम, वर्षा गुप्ता सहायक लेखाधिकारी, कविता बुन्देल कनिष्ठ अभियंता कार्यालय सचिव प्रशासन, अतिमा ईनाणी प्रशासनिक अधिकारी अजमेर डिस्कॉम, यह समिति कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कार्य करेगी और अजमेर डिस्कॉम में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक काम बतारवण सुनिश्चित करेगी। सचिव प्रशासन सीमा शर्मा ने कहा कि हमारी कंपनी में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यह समिति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

75वां राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया

भीलवाड़ा, (निर्स)। संगम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय विधि दिवस भारतीय संविधान को अपनाने की याद में मनाया जाता है। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश अजय शर्मा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) विशाल भारगवा और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) नागेन्द्र सिंह सहित विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। जिला न्यायाधीश अजय शर्मा ने संविधान के महत्व पर जोर देते हुए इसकी तुलना पतंग से की जो हमें ऊंचाईयां तक ले जाती है। एडीजे विशाल भारगवा ने भारतीय संविधान के इतिहास और कानूनी अधिनियम बनाने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की, जबकि सीजेएम श्री नागेन्द्र सिंह ने भी संविधान के इतिहास के बारे में बताया। कार्यक्रम कुलपति प्रो. (डॉ.) करुणेश सक्सेना; प्रो वाइस चांसलर प्रो. (डॉ.) मानस रंजन पाणिठाणी, रजिस्ट्रार प्रो. (डॉ.) राजीव मेहता और डीन विधि विभाग प्रो. (डॉ.) वीरेंद्र कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉ. ओमप्रकाश सोमकुंवर, डॉ. सुनाक्षी शर्मा, डॉ. गोवर्धन लाल पांडे, शशांक शेखर सिंह, आदित्य दाधीच, गौरव सक्सेना और वार्तिका मिश्रा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. विष्णुप्रिया दाधीच ने किया, जबकि एंकरिंग कश्मिरा मरवाहा ने की। स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज द्वारा आयोजित इस वर्ष के कार्यक्रम में पोस्टर-मेकिंग प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता शामिल थी। भाषण प्रतियोगिता में अभिनव जैन ने और पोस्टर-मेकिंग प्रतियोगिता में संजना कौशिक ने शीर्ष स्थान हासिल किया।

साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित

शाहपुरा, (निर्स)। जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में विभागों की कार्य प्रगति रिपोर्ट, परियोजनाओं व योजनाओं से संबंधित कार्यों की प्रगति, जनसुनवाई में प्राप्त विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण सहित विभिन्न बिंदुओं की जिला कलेक्टर द्वारा समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर शेखावत ने जिले से संबंधित विभागों की बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समय पर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने संबंधित प्रकरणों की समीक्षा कर समय पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग की झोलाझण्ड डॉक्टरों के खिलाफ विभिन्न चलाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए। इस दौरान विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

समस्याओं पर जांच दिया

शाहपुरा, (निर्स)। संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह चंपावत व महामंत्री जगेश्वर शर्मा एवं मुख्य संरक्षक संयुक्त कर्मचारी महासंघ के एकीकृत गजेंद्र सिंह राठौड़ ने शिक्षा मंत्री मदन दिलीवार को प्रबोधकों के अधिशेष होने पर आ रही समस्याओं पर ज्ञान दिया गया। इस पर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया की आपकी मांग को प्रमुखता से रखा जाएगा। मांग में अधिशेष प्रबोधक शिक्षकों को अधिशेष से पहले 6 एवं पदोन्नत की जाए, जिससे अधिशेष प्रबोधक शिक्षकों में आ रही समस्या का निराकरण हो सके। शारीरिक शिक्षक एवं शारीरिक प्रबोधक शिक्षक एवं प्रबोधकों को सेंकेंडरी सेटअप व इंग्लिश मीडियम में ही अधिशेष प्रबोधकों को वहीं पर पदस्थापन किया जाए, अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ के आईटी सेल प्रभारी एवं संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के ब्लॉक अध्यक्ष शाहपुरा गजराज सिंह राठौड़ सहित पदाधिकारी मौजूद रहे।

शिविर में 121 रोगीयों को दवा वितरण

मदनगंज-किशनगढ़, (निर्स)। सेवा भारती की ओर से धान मंडी स्थित केसरचंद चौधरी सेवा सदन में आयोजित निःशुल्क आयुर्वेदिक इलेक्ट्रोपैथी फिजियोथैरेपी शिविर में 121 रोगीयों की जांच कर दवा वितरण की गई। वैद्य कृष्णकुमार, गोविंद सहाय शर्मा, संतोष शुक्ल इलेक्ट्रोपैथी डॉ विनय सिंह चौहान, प्रवीण गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ सविता कश्यप, फिजियोथैरेपी से ताहिर मोईन ने सेवाएं दीं। जिलाअध्यक्ष गिरधर पुरोहित ने सेवा भारती के जन कल्याणकारी प्रकल्प के बारे में जानकारी दी। शिविर में जोड़ों में दर्द, गठिया बाई, मधुमेह, बीपी, अस्थमा, एलर्जी, पथरी आदि रोग से ग्रसित रोगीयों को दवा वितरित की। मंच संचालन जिला सहमंत्री राजेश नवहाल ने किया। इस दौरान संरक्षक सीताराम बंसल, दिनेश, करमचंद, विनोद, चनश्याम, भंवरलाल साहु, शंकर सोलंकी आदि मौजूद रहे।

परिषद का चार्ज लिया एसडीएम ने

पुष्कर, (निर्स)। पुष्कर नगर परिषद में भी निर्वाचित भाजपा बोर्ड का कार्यकाल सोमवार को खत्म हो गया था। जिसके पश्चात राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब पुष्कर एसडीएम गौरव मिश्रल यहां के मुख्य प्रशासक नियुक्त किया गया। मंगलवार को शाम मित्तल ने परिषद कार्यालय पहुंचकर प्रशासक का कार्यभार संभाल लिया। परिषद कार्यालय पहुंचने पर आयुक्त कीर्ति कुमावत ने उन्हें पुष्प भेंट कर स्वागत किया। इसी के साथ एसडीएम मित्तल ने अब एक और नई जिम्मेदारी ग्रहण कर ली। अब आगामी महीनों में होने वाले निकाय चुनावों के दौरान परिषद में एक बोर्ड का गठन होने तक मित्तल यहां प्रशासक की भूमिका निभाते रहेंगे। खास बात यह है कि पुष्कर परिषद बनने के बाद अब बावडों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष के पूर्व पार्षदों द्वारा भी अपने अपने मतभेद दूर करके इस दौरे में सहयोग देने का प्रयास कर रहे हैं।

कांग्रेस ने मनाया संविधान बचाओ दिवस

अजमेर, (कास)। संविधान दिवस पर कांग्रेस ने मंगलवार को संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस नेताओं ने अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहब भीमसेन अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और भाजपा पर निशाना साधा। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, अजमेर उतर विधानसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। रामचंद्र चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा नेता संविधान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाजपा की नीतियां और कार्य संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं। कांग्रेस को अपने मतभेद दूर करके इस दौरे में सहयोग देने का प्रयास कर रहे हैं। अजमेर उतर विधानसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता ने भी भाजपा पर हमला बोले।

कांग्रेस ने मनाया संविधान बचाओ दिवस बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन हुए कहा लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हमें संविधान बचाना होगा। भाजपा देश को बांटने का काम कर रही है और हम इसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। रलावता ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा को कांग्रेस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हर संभव प्रयास करेगी। कार्यक्रम में कांग्रेसी नेताओं ने संविधान की रक्षा और उसके महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान ही देश की एकता और अखंडता का आधार है और इसके संरक्षण के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए।

भारतीय ट्रेड यूनियन की ओर से राज्य स्तर पर विरोध दिवस मना कर मांग पत्र दिया

भीलवाड़ा, (निर्स)। जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू की ओर से राज्य स्तर पर विरोध दिवस मना कर मांग पत्र दिया गया। प्रांतीय प्रतिनिधि ओमप्रकाश देवानी ने बताया कि राज्य स्तरीय मांग पत्र में - (1) सरकार द्वारा लेबर कोड बनाने वापस लेने, (2) न्यूनतम वेतन 26000 पर लागू करने, (3) समान काम समान वेतन देने, (4) ठेका प्रथा को बंद करने, (5) आंगनबाड़ी योजना कर्मियों को स्थाई करने, (6) निर्माण श्रमिकों की योजनाओं की सहायता लागू करने, (7) भीलवाड़ा में बंद हुई टेक्सटाइल श्रमिकों का भुगतान दिलाया जाने आदि मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। देवानी ने बताया कि भीलवाड़ा में टेक्सटाइल प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों को बिना उतका हिंसाब दिए बाहर संस्थाओं को बंद किए जाने पर श्रमिकों ने आक्रोश व्यक्त किया। भीलवाड़ा स्थित मयूर फैब्रिक के प्रबंधक ने संस्थान को बंद कर दिया और श्रमिकों का भुगतान नहीं किया गया, इसी प्रकार अजय सिंटेक्स द्वारा अपने संस्थान की मशीनों को बंद कर दिया। श्रमिकों को अवैध रूप से सेवा



भीलवाड़ा में बंद हुई टेक्सटाइल श्रमिकों का भुगतान दिलाया जाने आदि मांगों को लेकर ज्ञापन दिया।

व्यक्त किया। भीलवाड़ा स्थित मयूर फैब्रिक के प्रबंधक ने संस्थान को बंद कर दिया और श्रमिकों का भुगतान नहीं किया गया, इसी प्रकार अजय सिंटेक्स द्वारा अपने संस्थान की मशीनों को बंद कर दिया। श्रमिकों को अवैध रूप से सेवा

पृथक कर दिया, सूरज यूनियंसल के श्रमिकों को भी प्रबंधन ने उनका समस्त हित लाभ का भुगतान नहीं दिया, एलडी शर्टिंग में भी अपनी संस्थान की मशीन को लेकर श्रमिकों में भारी आक्रोश रहा उन्होंने जिला कलेक्टर के माध्यम से

टेक्सटाइल के मालिकों द्वारा बिना किसी युक्तिपूर्वक कारण के श्रमिकों को सेवाओं का लाभ नहीं देकर कार्य से बेदखल किया जाता है, इन सब चीजों को लेकर श्रमिकों में भारी आक्रोश रहा उन्होंने जिला कलेक्टर के माध्यम से

युवती से पर्स लूट की वारदात

अजमेर, (कास)। अजमेर के क्रिश्चियन गंज थाना क्षेत्र में पर्स लूट की घटना सामने आई है। स्कूटी सवार दो बदमाश एक युवती को पर्स छीनकर फरार हो गए। पर्स में मोबाइल, आधार, पैन कार्ड, एटीएम और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। पीड़ित युवती ने मामले की शिकायत क्रिश्चियन गंज थाने में दर्ज करवाई है। क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस के अनुसार, गौरी नगर निवासी ऋचा सिंह ने बताया कि वह ईदगाह रोड स्थित एक मेडिकल स्टोर से दवा लेकर वापस आ रही थी। इस दौरान स्कूटी पर सवार दो बदमाशों ने झपट्टा मारकर उसका पर्स छीन लिया। ऋचा सिंह ने बताया कि उसने बदमाशों का पीछा किया और चिल्लाई, लेकिन दोनों बदमाश तेजी से भाग निकले। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पर्स में उसका मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम और नगदी सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। घटना की सूचना मिलने पर क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

राष्ट्र की आत्मा है भारतीय संविधान : ज़िला कलेक्टर

शाहपुरा, (निर्स)। संविधान दिवस के अवसर पर मंगलवार को प्रताप सिंह बारहठ राजकीय महाविद्यालय द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने भारतीय संविधान की विशिष्ट विशेषताओं पर केंद्रित विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थियों ने संविधान से संबंधित विषयों जैसे प्रस्तावना, संशोधन, अनुच्छेद, रिट, विभिन्न विधेयक, नीतियां, महत्वपूर्ण मामले जिनके कारण संविधान में संशोधन हुआ आदि पर बात की। देश में वर्तमान उथल-पुथल के मद्देनजर, यह महसूस किया गया कि संविधान की विचारधारा और समय की बदलती जरूरतों को दर्शाने वाले नए विचारों का समिश्रण लाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य पी आर मीणा सहित कॉलेज की अन्य फेकेल्टी ने संविधान विषय पर अपने विचार रखें तथा शपथ ग्रहण का भी आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने इस संगोष्ठी में

प्रताप सिंह बारहठ राजकीय महाविद्यालय में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित

पहुँच कर सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए बताया कि किस तरह भारतीय संविधान हमें सशक्त बनाता है। उन्होंने कहा कि संविधान में जिन अनुच्छेदों और सूचियों का उल्लेख किया गया है, वह प्रत्येक देशवासी के जीवन में उपयोगी है। शिक्षा के साथ-साथ रोजगार प्राप्ति और जीवनयापन में भी भारतीय संविधान की महत्ता और उपयोगिता सदैव बनी रहेगी। जिला कलेक्टर ने संविधान को राष्ट्र की आत्मा बताते हुए कहा कि संविधान प्रत्येक

संविधान दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया

मसूदा, (निर्स)। मंगलवार को पंचायत समिति परिसर में संविधान दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। मसूदा विकास अधिकारी संदेश पाराशर ने संविधान के महत्व और इसके प्रावधानों पर चर्चा की गई। संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार प्रस्तुत किया इसके महत्व को समझने का प्रयास किया और कहा कि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है।

यह दिन भारतीय संविधान के अपनाए जाने की याद में मनाया जाता है, जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और कहां संविधान दिवस हमें हमारे देश के संविधान के महत्व को समझने और इसके प्रावधानों का पालन करने का अवसर प्रदान करता है। हमें अपने देश के संविधान को समझना चाहिए और इसके प्रावधानों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे देश की आधारशिला है। और यह हमें न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के मूल्य की याद दिलाता है।

देशवासी को सशक्त बनाने के साथ-साथ जागरूक भी करता है। जिला कलेक्टर ने विद्यार्थियों को संविधान के महत्व के बारे में बताते हुए संविधान के द्वारा प्रदान किए गये मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों, डीपीएसपी, विभिन्न एक्ट, संविधान संशोधन सहित विभिन्न प्रावधानों के बारे में विद्यार्थियों से विस्तार में चर्चा की। संगोष्ठी में विभिन्न प्रावधानों का विश्लेषण किया गया और सुझाव दिए गए। स्वतंत्रता, विकेंद्रीकरण और समानता को भारतीय विचारधारा संविधान में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। दर्शकों को भारतीय संविधान के महत्व, दोषों और सुझावों को प्रभावित करने वाले एक लंबे सत्र के बाद संगोष्ठी समाप्त हुई। इस दौरान संविधान पर आधाजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। तथ्या प्रश्नोत्तरी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान समाज कल्याण अधिकारी राम अंबतार जाट, महाविद्यालय स्टाफ सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे।

भारत सरकार द्वारा संचालित मेड़ता स्किल इंडिया का शुभारंभ

मेड़ता सिटी, (निर्स)। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है स्किल इंडिया मिशन के तहत मंगलवार को आहिददाया मदरसा समिति मेड़ता के द्वारा ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में शुरू किए गए स्किल इंडिया मिशन की फ्रेंचाइजी का शुभारंभ हुआ इस मौके पर पूर्व विधायक रामचंद्र जाड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश नारायण शर्मा



कॉलेज का उद्घाटन करते हुए अतिथि।

पैरामेडिकल कोर्स की मिलेगी सीमागत

विधायक प्रतिनिधि कलरू सरपंच अशोक जुरिया, शिवरतन वाल्मीकि, चैयरेमैन सलीम मोयल, पूर्व चैयरेमैन रस्तम अली प्रिंस, इत्यादि ने संबंधित करते हुए कहा कि यह राजस्थान की पहली ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में संस्था शुरू की गई है जो डीएमएलटी, सीएमएलटी, लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिकल के कोर्सज करवाएगी। जिससे बच्चे अपना करियर बना पाएंगे और आज के युग कंपटीशन का युग है। ऐसे में इस तरह की कोशिश का मेड़ता में शुभारंभ होना वाकई एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो की नागौर में ही नहीं राजस्थान की प्रथम प्रकार की संस्था होगी जो

पैरामेडिकल कोर्स स्किल इंडिया मिशन के तहत करवायेगी। आए हुए मेहमानों का साफा और माला पहनकर स्वागत किया गया और उसके बाद नागौर चौकी पर स्थित अहमदिया मदरसा समिति की ओल्ड बिल्डिंग में फीता काटकर शुभारंभ

किया गया। इस मौके पर पार्षद प्रतिनिधि सलीम शेरोनी, जीसान कुर्शी, अमजद केके अहमदिया मदरसा समिति के अध्यक्ष अजीज खां भाटी, सचिव रियाज मोहम्मद खान, उपाध्यक्ष शबीर शेरोनी, अब्दुल रहमान बेहेलीम, मेड़ता कांग्रेस नगर अध्यक्ष जाकिर खान

सांखला, उमर प्रिंस, सरदार खान जोया, शब्बीर शेरोनी, हारून रिजवी, डॉ आर के तंवर, इस्लाम पटान, खुशीद भाई, अमीन, महेंद्र जयपाल, मुन्ना भाई गहलोत, मजीद भाई, बाबू भाई, हबीब खान, सहित समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

विशेष ग्राम सभा का आयोजन

अराई, (निर्स)। ग्राम पंचायत कटसुरा में मंगलवार को इस वर्ष 26 नवंबर को संविधान लागू होने के 75वें वर्ष के उत्सव के रूप में मनाए जाने के उपलक्ष्य में सरपंच राधा देवी की अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत द्वारा बताया गया कि ग्राम सभा में उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों को संवैधानिक मूल्य पर प्रश्नोत्तरी स्वयं सहायता समूह एसएचजी के साथ जुड़ाव आदिवासी समुदायों में क्षमता निर्माण एवं संविधान से संबंधित अधिकारों और कर्तव्य से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। ग्राम सभा में सरपंच राधा देवी ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत सीओ मंद्राज देवी पटवारी प्रकाश शर्मा प्रिया अग्रवाल पशु चिकित्सक मंद्राज समजसेवी हिंदिन घासल हदयाल जाखड़ लादूराम नामा सहित कर्मचारी वार्डपंच ग्रामीणजन ग्राम सभा में उपस्थित हुए।

भीलवाड़ा। संविधान दिवस के अवसर पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग तथा शिक्षा विभाग के तत्वावधान में मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेन्द्र मार्ग विद्यालय में संगोष्ठी का आयोजित की गई व सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा संविधान के इतिहास, इसके प्रावधानों और इसके महत्व को दर्शाने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी में जनसम्पर्क अधिकारी हेमन्त छोपा, प्रधानाचार्य श्याम लाल खटीक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के वरिष्ठ सहायक रोहित वर्मा सहित स्कूल के शिक्षकों सहित छात्रों ने भाग लिया। जनसम्पर्क अधिकारी हेमन्त छोपा ने बताया कि इस संगोष्ठी में संविधान के महत्व और इसके प्रावधानों पर चर्चा

प्रदर्शनी से विद्यार्थियों को बताया भारतीय संविधान का इतिहास



संविधान दिवस के अवसर पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग तथा शिक्षा विभाग की संगोष्ठी का आयोजन।

की गई। वक्ताओं तथा छात्रों ने संविधान के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए और इसके महत्व को समझने का प्रयास किया। इस दौरान

वक्ताओं ने बताया कि संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता

संविधान दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन

है। यह दिन भारतीय संविधान के अपनाए जाने की याद में मनाया जाता है, जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य श्यामलाल खटीको ने कहा, संविधान दिवस हमें हमारे देश के संविधान के महत्व को समझने और इसके प्रावधानों का पालन करने का अवसर प्रदान करता है। हमें अपने देश के संविधान को समझना चाहिए और इसके प्रावधानों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे देश की आधारशिला है और यह हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और बंधुत्व के मूल्यों की याद दिलाता है।

पासपोर्ट प्राधिकरण पुलिस रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है : हाईकोर्ट

‘प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट अपने आप में पासपोर्ट लेने से नहीं कर सकती वंचित’

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अपने आप में किसी नागरिक को पासपोर्ट प्राप्त करने के उसके कानूनी अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसके अलावा पासपोर्ट प्राधिकरण पुलिस की प्रतिकूल सत्यापन रिपोर्ट मानने के लिए ही बाध्य नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने केन्द्र सरकार और पासपोर्ट अधिकारी को कहा है कि वह याचिकाकर्ता के पासपोर्ट नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र 8 सप्ताह में तय करे। हालांकि अदालत ने पासपोर्ट विभाग को छूट दी है कि यदि मामले में कुछ

प्रतिकूल मिले तो वे विधिनसार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। जस्टिस अनूप डंड की एकलपीठ ने यह आदेश सावित्री शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक को उसके पासपोर्ट प्राप्त करने या नवीनीकरण करने के कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने का निर्णय केवल पासपोर्ट प्राधिकरण की ओर से ही लिया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राकेश चंदेल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का पासपोर्ट मई, 2022 तक वैध था। ऐसे में उसने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए विभाग में आवेदन किया, लेकिन पुलिस सत्यापन जांच रिपोर्ट में संदेह होने पर उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए पासपोर्ट नवीनीकरण का आग्रह किया गया। जवाब में विभाग की ओर से अधिवक्ता मनजीत कौर ने बताया कि क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस, नई दिल्ली ने याचिकाकर्ता की पुलिस सत्यापन जांच करवाई थी। इसमें उसकी राष्ट्रीयता संदेहपूर्ण व नेपाली आई है। इस रिपोर्ट

पर ही उसके पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं किया। इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके दादा नेपाल में रहते थे, लेकिन याचिकाकर्ता का जन्म भारत में हुआ है। उसकी शादी 2017 में यहीं हुई है। उसके दो बच्चे हैं और वह भारत की नागरिक है। इसलिए केवल पुलिस की प्रतिकूल जांच रिपोर्ट पर उसके पासपोर्ट नवीनीकरण से मना नहीं कर सकते। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस जांच रिपोर्ट के प्रतिकूल होने मात्र से पासपोर्ट से वंचित नहीं करने को कहा है।

आर.सी.डी.एफ. को दिल्ली में मिले दो बड़े पुरस्कार



राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत सरकार की ओर से आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक समिति को श्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ दुग्ध संघ के दो कर्मचारी राजेन्द्र कुमार और वीरन्द्र कुमार सैनी को बेस्ट एआई टैक्नीशियन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया।

नई दिल्ली/जयपुर। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में आरसीडीएफ की धूम रही। एक ओर जहाँ, आरसीडीएफ से सम्बद्ध भोलवाडा दुग्ध संघ की प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक समिति को श्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ दुग्ध संघ के दो कर्मचारी राजेन्द्र कुमार और वीरन्द्र कुमार सैनी को बेस्ट एआई टैक्नीशियन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया।

प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज ने राष्ट्रीय स्तर के इन पुरस्कारों के लिये प्रदेश की सहकारी डेयरीयों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों और डेयरी कर्मचारियों को बधाई देते हुए इसे उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत का फल बताया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी आरसीडीएफ एवं इससे सम्बद्ध जिला दुग्ध संघों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में आयोजित एक समारोह में भोलवाडा की दुग्ध उत्पादक लाभाधी माया देवी और आरसीडीएफ की

पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज यहाँ नई दिल्ली स्थित मानेकशा सेन्टर में आयोजित राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर आयोजित एक भव्य समारोह में यह पुरस्कार वितरित किये। पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में गोपाल रत्न राष्ट्रीय अवार्ड एक प्रतिष्ठित अवार्ड है। विजेताओं का चयन देशभर से 2574 ऑनलाइन आवेदकों में से किया गया था। आरसीडीएफ की प्रशासक और प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज ने राष्ट्रीय स्तर के इन पुरस्कारों के लिये प्रदेश की सहकारी डेयरीयों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों और डेयरी कर्मचारियों को बधाई देते हुए इसे उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत का फल बताया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी आरसीडीएफ एवं इससे सम्बद्ध जिला दुग्ध संघों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में आयोजित एक समारोह में भोलवाडा की दुग्ध उत्पादक लाभाधी माया देवी और आरसीडीएफ की

संविधान के प्रति अश्रद्धा पैदा ना करें : देवनानी

जयपुर। विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि संविधान के प्रति अश्रद्धा पैदा ना करें। संविधान के मूल ढांचे को कोई बदल नहीं सकता है। संविधान के 22 भागों में हमारी संस्कृति और नैतिकता का विवरण है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक संविधान को पढ़ें, उसे जानें और उसके अनुकूल जीवन जीने का प्रयास करें। संविधान हमारी आत्मा और पवित्र ग्रंथ है। यह हमारे जीवन मूल्य व संस्कृति का स्वाभिमान भी है। संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक भारत के लोगों की आकांक्षाओं, मूल्यों और आदर्शों का प्रतिबिम्ब है। देवनानी मंगलवार को विधानसभा में संविधान दिवस पर आयोजित समारोह में राजनैतिक आख्यान संग्रहालय में नवनिर्मित संविधान दीर्घा का लोकार्पण किया। इस संविधान दीर्घा में मूल संविधान के 22 भागों के आरम्भ में दर्शायी गयी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। देवनानी ने बताया कि संविधान दीर्घा का उद्देश्य आमजन और युवाओं में राष्ट्र और राष्ट्र के संविधान का बोध कराने के साथ ही संविधान, सांस्कृतिक और नैतिकता के प्रति जागरूकता लाना है। उन्होंने संविधान दिवस को संविधान निर्माताओं के प्रति श्रद्धाभाव प्रकट करने तथा उनके अविस्मरणीय योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का स्मरण दिवस बताया है।



विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को विधानसभा में संविधान दीर्घा का लोकार्पण किया।

लिया। देवनानी ने अधिवक्ताओं का आवाहन किया कि वे संविधान प्रदत्त अधिकारों की पालना कराने में सहयोगी बनें। संविधान की आत्मा और डॉ. अंबेडकर की अपेक्षाओं के अनुरूप आज के समय की आवश्यकता के अनुसार लोगों को शीघ्र न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले, संविधान की रक्षा हो, संविधान में निष्ठा हो और हम सभी असंवैधानिक कार्यों से बचें। उन्होंने समाज और राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए कहा।

देवनानी ने कहा कि संविधान के 22 भागों के मुख पृष्ठ पर भारत की संस्कृति और स्वामित्व को दिखाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि इन तस्वीरों में भारत की प्राचीन सभ्यता मोहन जोदड़ो से लेकर महाभारत में

कुरुक्षेत्र और कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के ज्ञान, भगवान श्री राम की लंका विजय, भगवान बद्ध का जीवन चरित्र, महान सम्राट अशोक, उज्जैन के न्यायिक महाराज विक्रमादित्य के राजदरबार, प्राचीन वैदिक गुरुकुल, नालंदा विश्वविद्यालय, भगवान महात्मा गान्धी के संघर्ष के साथ ही झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, छत्रपति वीर शिवाजी और गुरु गोविन्द सिंह को प्रदर्शित किया गया है।

देवनानी ने कहा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लम्बा और लिखित संविधान है। यह हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का इतिहास उन लाखों भारतीयों के संघर्षों और स्वतंत्र होने की आशाओं में निहित है जो स्वतंत्रता, न्याय एवं समानता के लिए लड़ते रहे थे। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, बाबा साहेब अंबेडकर, वीर सावरकर जैसे महापुरुषों के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत की प्राप्ति के लिए आशा की चिंगारी जलाई थी।

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2023 को लेकर बहस पूरी



उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को केन्द्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2023 में पदों के 15 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाने से जुड़े मामले में दायर याचिका पर बहस पूरी हो गई है। अदालत ने दोनों पक्षों को बहस सुनकर मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश अर्जुन सिंह शेखावत व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रघुचंद्र शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से पुलिस कांस्टेबल के पदों पर गत वर्ष भर्ती निकाली गई। जिसमें सीनियर सैकण्डरी स्तर की सभ्यता पात्रता परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को कांस्टेबल भर्ती के विज्ञापित कुल पदों के मुकाबले 15 गुणा को बुलाना था।

उन्होंने केन्द्र सरकार से आंगनवाड़ी भवनों के हर पाँच साल में जारी होने वाली 3000 रुपये की मरम्मत राशि को भी जरूरत के अनुसार बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्रों की मरम्मत को लागत 50 हजार से एक लाख तक हो सकती है। उपमुख्यमंत्री ने अपने पत्र में वर्ष 2023-24 के 34.38 करोड़ के केन्द्रों तथा किशोरी बाल योजना के अन्तर्गत तीसरी त्रैमासिक अनुदान की किस्त जारी करने और 340 आंगनवाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्रों के रूप में विकसित करने की स्वीकृति जारी करने की भी मांग की। दिया कुमारी ने केन्द्रीय मंत्री से मांग करते हुए कहा कि राज्य को एकमुस्त राशि मिलने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है : राजदीपक रस्तोगी



अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय, भारत सरकार के अन्य वकील एवं एनजीओ हेल्प्स की ओर से राजस्थान सेंटर झालाना के सभागार में 75वां संविधान दिवस कार्यक्रम मनाया गया।

था और 75 वर्ष पूर्ण होने पर यह संविधान का अमृत महोत्सव है। रस्तोगी ने प्राचीनकाल में विद्यमान रही न्यायिक व्यवस्थाओं से लेकर वर्तमान में भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला और बताया कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसका संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है और बिना किसी भ्रम, जाति या आर्थिक आधार के समस्त नागरिकों को

एक से अवसर प्रदान करने का भी कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत जीवन जीने का अधिकार विषय पर भी प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि के रूप में बोलेते हुए न्यायाधीश समीर जैन ने संविधान को रामायण और महाभारत के समकक्ष एक पवित्र ग्रन्थ बताया और उसके विभिन्न आयामों पर चर्चा करते हुए वहाँ उपस्थित वकील समुदाय को आह्वान किया कि इस विषय पर सार्थक चर्चा

तब ही हो सकती है जब आपस में मिल बैठकर विचार किया जावे जिस पर भारत सरकार के कई अधिवक्ताओं द्वारा विभिन्न प्रश्न किये गये जिनका उत्तर न्यायाधीश समीर जैन ने दिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलेते हुए न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन ने संविधान निर्माण के इतिहास पर पकड़ा डालते हुए संविधान में मौजूद मूलभूत अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के महत्व पर भी प्रकाश डाला और यह भी

रामपुर फाटक पर बनेगा ओवर ब्रिज

जयपुर। सांगानेर विधानसभा में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। उसमें विधायक भजनलाल शर्मा सांगानेर विधानसभा में लगातार सांगानेर पर सांगत देने का कार्य करते हैं। इस श्रृंखला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामपुर फाटक सांगानेर रेलवे स्टेशन पर लगातार यातायात के दबाव और जनता को घंटों रामपुर फाटक पर इंतजार करते देख रामपुर फाटक पर पुलिया और लो हाइट सबवे बनाने का फैसला लिया है।

‘बाँडी बदलाव वाली बसों को सड़क पर चलने की नहीं दे सकते मंजूरी’

जयपुर। हाईकोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम और एआईएस नियमों की अवहेलना कर बाँडी में बदलाव करने वाली बसों को आमजन की सुरक्षा को देखते हुए सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि इन बसों के चलने की छूट दी गई तो इससे ना केवल कानूनी नियमों की अवहेलना होगी, बल्कि यह आमजन की सुरक्षा के लिए भी खतरा होगा। अदालत ने याचिकाकर्ता बस संचालकों को छूट दी कि वे संबंधित परिवहन अधिकारी के यहाँ से अपनी बसों की बाँडी में बदलाव करने के लिए उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नियमों की अवहेलना कर वे बसों का संचालन नहीं कर सकते। जस्टिस अनूप कुमार डंड ने यह आदेश हेरन्ड सिंह व अन्य की याचिकाओं पर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता बस संचालक तय अवधि में अपनी बसों की बाँडी में बदलाव नहीं कर पाए तो ऐसी स्थिति में विभाग उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया : जूली

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार जयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर आर तिवारी ने मंगलवार को संविधान दिवस 26 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर विचार गोष्ठी एवं सभा का आयोजन किया गया।

मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मुख्य वक्ता पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी बीएम शर्मा, विधायक एवं सचेतक रफीक खान, विशिष्ट अतिथि सत्येंद्र सिंह रावत पूर्व अतिरिक्त महासचिव एवं पूर्व ललित तुन्वाल, संगठन महासचिव, प्रदेश कांग्रेस आदि ने संबोधित किया।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया और अपने अधिकारों के लिए लड़ने हेतु कानून बनाया और उन्होंने संविधान दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर आर शर्मा, उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीना, पूर्व संसद अयक अली टाक, पूर्व अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड अर्चना शर्मा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जसवंत गुर्जर, स्वर्णिम चतुर्वेदी, सचिव अयूब खान, जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी मोहम्मद सलीम, किनय पात जादौन, पी डी शर्मा, जगदीश शर्मा, अतुल पारस, हर्देर पाल सिंह जादौन, युगल किशोर शर्मा, जावेद सेठी, राजीव चौधरी, रतन सैनी, रोहतास सिंह, राजकुमार शर्मा, कैलाश खारडा, रामावतार मोरार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता ब्लाक अध्यक्ष, मण्डल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, पार्षद, पार्षद प्रत्याशी, पूर्व पार्षद, चारों ग्रामिण संगठन सेवादल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई छात्र संगठन के पदाधिकारी एवं तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं उपस्थित थे।

'संविधान हमें अधिकारों के साथ कर्तव्य की सीख देता है'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने "संविधान दिवस" कार्यक्रम में भाग लिया

जयपुर, 26 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार संविधान में निहित लोक कल्याण की मूल भावना को सर्वोपरि मानते हुए प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से संविधान की मूल भावना को साकार

■ मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल ने मंत्रियों, प्रेम चन्द बैरवा, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, हेमन्त मीणा, सुरेश रावत, बाबूलाल खराडी व अविनाश गहलोत तथा मुख्य सचिव सुधांशु पंत, विभिन्न विभागों के अति. मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भाग लिया। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों से संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित "संविधान दिवस कार्यक्रम" का दीप जलाकर शुभारम्भ किया।

किया। शर्मा ने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे प्रभावी संविधान है। यह हमारे लोकतंत्र का आधार होने के साथ ही, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मार्गदर्शक भी है। इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि संविधान हमें अधिकार देने के साथ ही, कर्तव्यों की भी सीख देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 नवम्बर, 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था और 26 जनवरी, 1950 को ये लागू हुआ, लेकिन संविधान दिवस मनाने की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की। प्रधानमंत्री ने इस दिन को चुनकर हमें यह स्मरण कराया कि संविधान हमारे देश की आत्मा है और इसकी सुरक्षा और सम्मान हमारा प्रथम कर्तव्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान निमार्ण में बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान के अन्य महान

शिल्पियों का अतुलनीय योगदान है। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए अभियान चलाने जैसे प्रयास राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा, हमारा संविधान केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा का प्रतिबिंब है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपस्थित

लोगों को संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विधि एवं विधिक संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराडी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

29 नवम्बर को कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नेताओं को दण्डित करें तथा हटायें तथा पार्टी को चुनावी लड़ाई के लिये उपयुक्त इकाई का रूप दें। राहुल को आत्मनिरीक्षण करने तथा सही कदम उठाने की जरूरत है, अन्यथा पार्टी की स्थिति, वर्तमान स्थिति से भी ज्यादा खराब हो सकती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निर्णयों को टालते जाने का समय जा चुका है तथा समय आ गया है कि पार्टी को रास्ते पर लाया जाये तता जैसा भी हो, ई.वी.एम. के मुद्दे पर दो-टुक रूख अपनाया जाये।

तेलंगाना सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। पर हमने अभी तक किसी भी दानदाता से फंड हस्तांतरण के लिए नहीं कहा था क्योंकि युनिवर्सिटी को सैकशन 80 जी के तहत आयकर से छूट नहीं मिली थी। चूंकि छूट का आदेश हाल ही में आया है, पर मुझे मुख्यमंत्री ने कहा है कि मौजूदा हालात और विवादों को देखते हुए फंड स्वीकार न किया जाए।

गौरतलब है कि 18 अक्टूबर को गौतम अडानी ने राज्य के मुख्यमंत्री रैवन्त रेड्डी को राज्य में युनिवर्सिटी बनाने के लिए 100 करोड़ रु. का चेक दिया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा कि "अडानी फाउण्डेशन का एक प्रतिनिधिमंडल गौतम अडानी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिला तथा 'यंग इंडिया स्किल्स युनिवर्सिटी' के लिए उन्होंने 100 करोड़ रु. का चेक दिया।"

इस पर राज्य में विपक्षी बी.आर.एस. ने और केन्द्र में भाजपा ने कांग्रेस पर दोहरे मानदंड का आरोप लगाया।

बी.आर.एस. के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने एक्स पर लिखा कि एक ओर तो राहुल गांधी और कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अडानी को "मोदानी" कहते हैं और उनकी दोस्ती का विरोध करते हैं लेकिन तेलंगाना में रैवन्त और अडानी "रैवडानी" दिख रहा है, क्या इसे राहुल गांधी और अडानी "रागाडानी" कहा जाए। उनकी पार्टी ने अडानी ग्रुप के सभी निवेशों को कैसिल करने की मांग की, जिसमें ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर व सीमेंट उद्योग के निवेश शामिल हैं।

भाजपा आई.टी. सैल के अमित मालवीय ने कहा, राहुल गांधी के लिए शर्म की बात है कि उनकी अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री, अडानी की बात आए तो राहुल को तबज्जो नहीं देते, भले ही राहुल गांधी दिन भर अडानी-अडानी चिल्लाते रहें।

सोरेन 28 नवम्बर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जे.एम.ए. ने राज्य के विधान सभा चुनावों में 81 में से 34 सीटें तथा कांग्रेस ने 16 सीटें जीती हैं।

महागठबंधन ने कुल 56 सीटें जीती हैं तथा 44.33 प्रतिशत वोट हासिल किये हैं। महागठबंधन में शामिल आर.जे.डी. ने 4 तथा सी.पी.आई. (मार्क्सवादी लेनिनवादी) ने 2 सीटें जीती हैं। भाजपा ने इस चुनाव में 21 तथा उसके नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एन.डी.ए.) ने कुल 24 सीटें जीती हैं।

'पूर्व सी.जे.आई. चन्द्रचूड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जबकि प्रतिद्वंद्वी खेमे ने जवाबी याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने विधान सभा स्पीकर राहुल नारवेकर से "डिस्क्वालिफिकेशन" याचिकाओं पर निर्णय लेने को कहा। इस वर्ष जनवरी में, स्पीकर ने शिंदे घटक को "असली शिवसेना" घोषित कर दिया।

राजत के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, पूर्व सी.जे.आई. ने आगे कहा, "यह तर्क हमेशा दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक केस क्यों नहीं ले रहा है, जो बीस वर्षों से लंबित है? या, क्यों एक

विशेष केस की सुनवाई नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट की मैनपावर सीमित है और इसमें बैलेंस करना पड़ता है।"

अपने कार्यकाल के संदर्भ में बोलते हुए चंद्रचूड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉण्ड्स, अलोगद मुस्लिम युनिवर्सिटी केस, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के तहत मदरसों को बंद करने, सिटिजनशिप एक्ट के सैक्शन 6-ए की वैधता, जैसे महत्वपूर्ण केसों में फैसले दिए।" क्या यह कम महत्वपूर्ण था।" पूर्व सी.जे.आई. ने आगे कहा, "हम उस एजेंडा पर नहीं चलते, जो दूसरे हमारे लिए तय करते हैं।"

बांग्लादेश में इस्काँन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हिंदू समुदाय के लोगों और चटगांव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुशाल बरन पर भी हमला हुआ है। इस मामले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कई लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है।

चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद इस्काँन ने एक्स पर एक पोस्ट किया। जिसमें कहा, हमें चिंताजनक खबर मिली है कि इस्काँन बांग्लादेश के प्रमुख नेता चिन्मय कृष्ण दास को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस्काँन भारत सरकार से तुरंत कदम उठाने और बांग्लादेश सरकार से बात करने की अपील करता है। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार चिन्मय कृष्ण दास को जल्द रिहा करे।

बता दें कि, इसी साल 30 अक्टूबर को बांग्लादेश में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में देशद्रोह अधिनियम के तहत चिन्मय कृष्ण दास प्रभु समेत 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है।

आरोप है कि 25 अक्टूबर को चटगांव के लालदीधी मैदान में सनातन जागरण मंच ने आठ सूत्री मांगों को लेकर एक रैली की थी। इस दौरान एक चौक पर स्थित आजादी स्तंभ पर कुछ लोगों ने भगवा ध्वज फहराया था। इस ध्वज पर आमी सनातनी लिखा हुआ था। इसे लेकर चिन्मय कृष्ण दास पर राष्ट्रीय झंडे की अवमानना व अपमान करने का आरोप लगाया गया है।

कनक भवन के मालिकाना हक से जुड़े ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राज्यों के भारत में विलय होने के पश्चात सरकारी संपत्ति बन गई थी। वहीं रामबाग, लिलिपूल और उसके आसपास की संपत्ति "कोवोनेंट" (राजस्थान का भारत में विलय होने से जुड़ी संधि) के अनुसार राजपरिवार की संपत्ति है।

कनक भवन के मालिकाना हक के लिये रामशरण गुप्ता व अन्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में आदेश दिये थे कि कनक भवन के मामले में हाईकोर्ट या कोई भी अदालत किसी भी तीसरी पार्टी के आवेदन पर कोई भी मुकदमा नहीं सुनेगा। अदालत ने यह भी कहा कि बार-बार हुए मुकदमों में अदालतें कई बार कह चुकी हैं कि इस संपत्ति के

वेचान के लिये अनुबंधन अमान्य है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रामशरण गुप्ता व अन्य ने वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में रिट याचिका भी दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना याचिका भी शुरू की थी, जिसे तभी वापिस लिया गया, जब इन लोगों ने अदालत से बिना शर्त माफी मांग ली थी। वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 2017 के आदेश पर दायर रिट्यू याचिका भी खारिज कर दी गई।

हरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इतने आदेशों के बावजूद वर्ष 2022 में हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर कनक भवन के मूल मालिक, ब्रिगेडियर

जे.डी.सी. आनंदी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के गिरफ्तारी वारंट जारी किए। परिवारी की ओर से आयोग को बताया गया कि उपभोक्ता आयोग ने उसके मामले में 10 नवंबर 2023 को जे.डी.ए. को निर्देश दिया था कि वह उसकी जमा कराई गई राशि 2,02,613 रुपये व इस राशि पर नौ प्रतिशत ब्याज सहित रकम लौटाए। इसके अतिरिक्त, परिवारी को हुई परेशानी के लिए 40 हजार रुपये अलग से दे, लेकिन विपक्षी ने आयोग के आदेश की पालना नहीं की। इस पर परिवारी ने 25 जनवरी 2024 को उसे कानूनी नोटिस भी भेजा। इसके बाद भी विपक्षी ने आयोग के आदेश की पालना नहीं की है। विपक्षी का ऐसा करना आयोग के आदेश की अवमानना करना है। इसलिए आदेश की पालना करवाई जाए।

गौरतलब है कि आयोग ने पूर्व में जे.डी.सी. के जमानती वारंट जारी किए थे, लेकिन आयोग के आदेश की पालना नहीं की गई। ऐसे में अब आयोग ने जे.डी.सी. के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

सड़कों पर उतरे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इमरान खान की पार्टी पी.टी.आई. के समर्थक इस्लामाबाद के डी-चौक स्थल की ओर जाने वाले रास्ते में लगाए गए अवरोधों को हटा रहे हैं। 'रेडियो पाकिस्तान' ने बताया कि सोमवार देर रात इस्लामाबाद में श्रीनगर राजमार्ग पर एक वाहन द्वारा टक्कर मारे जाने से पाकिस्तान 'पैजर्स' के चार अधिकारियों की मौत हो गई।

किया है।

शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित "संविधान दिवस कार्यक्रम" को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज का दिन संविधान की महिमा का उत्सव और उन महान व्यक्तित्वों को याद करने का दिन है, जिन्होंने इस अद्भुत दस्तावेज का निर्माण

क्या अवास्तविक रिटर्न का वादा करने वाली योजनाओं में आपके पैसे डूब गए हैं?

वित्तीय मामलों से जुड़ी अपनी शिकायतें सचेत पोर्टल पर दर्ज करें

- यह पोर्टल वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- सचेत पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

अपनी शिकायतें <https://sachet.rbi.org.in> पर दर्ज करें

अधिक जानकारी के लिए, <https://bikethatai.rbi.org.in/sachet> पर क्लिक करें

जनहित में जारी
भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना

श्री नरेन्द्र मोदी
श्री भजनलाल शर्मा

आवेदन आमंत्रित

निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर द्वारा RKCL के माध्यम से बालिकाओं और महिलाओं के लिए कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों का निःशुल्क प्रशिक्षण

RS-CIT आधारभूत कंप्यूटर प्रशिक्षण	RS-CFA GST, Tally आधारित वित्तीय लेखांकन प्रशिक्षण	RS-CSEP स्पोकन इंग्लिश एवं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रशिक्षण
---	--	---

योजना के तहत आवेदन www.myrkcl.com/wcd पर किया जा सकता है।

आवेदन की अंतिम तिथि 16-12-2024

योजना एवं चुनिंदा आईटी ज्ञान केन्द्र की जानकारी www.wcd.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

निदेशालय महिला अधिकारिता
महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार